पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है । मंत्री जी ने अपने जवाब में जो आंकड़े दिये हैं, उसमें 2001-2002 में 20 करोड़ रूपए और 2002-2003 में लगभग 28 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमालय प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाने का क्या वे प्रावधान करेंगे ?

श्री काशीराम राणा : माननीय सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में जो भी परिस्थिति पैदा होती है , उसको ख्याल में रखकर जो भी वहां से डिमांड आती है , उसके अनुसार ठीक ढंग से हम फंड अलॉट करते रहते हैं । जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है , अगर वहां कोई विशेष परिस्थिति हो और उस परिस्थिति में इस बारे में हमारे पास कोई प्रस्ताव आएगा तो हम अवश्य इसके बारे में सोचेंगे ।

श्री कृपाल परमार : महोदय, हिमाचल प्रदेश में नार्थ ईस्ट के बाद सबसे ज्यादा बारिश होती है लेकिन यहां पर रेन हारवैस्टिंग से पानी को इक्ट्ठा करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की क्या सरकार कोई योजना बनाएगी और इसका "ख " भाग है कि जब तक इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होगी, यह काम सफल नहीं हो पाता है । क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी कि रेन हारवैस्टिंग के कार्यक्रम में लोगों की भागादारी सुनिश्चित करे ।

श्री कांशीराम राणा : माननीय सभापति महोदय, हमारी जो भी योजनाएं अभी चल रही हैं , चाहे वॉटरशेड स्कीम हो या रेन हारवैस्टिंग की योजना हो , हम बहुत बड़े पैमाने पर योजनाओं को लेते हैं । इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने स्वजल धारा योजना भी उसके अंतर्गत चलाई है । माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है , इसके बारे में हमने रिप्लाई किया है । पानी के बारे में अगर कोई समस्या हो तो जैसा मैंने पहले जवाब दिया है कि हम अवश्य उसके बारे में पॉज़िटिवली सोचेंगे ।

*45. [The questioners (SHRI KALRAJ MISHRA and DR. AKHILESH DAS): were absent, for answer *vide* page 297

Low cost housing for textile workers

*46. SHRIMATI S.G. INDIRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have taken up building of low cost houses for textile workers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SYED SHAHNAWAJ HUSSAIN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Central Government has housing schemes to provide housing for the economically weaker sections of the society. The Ministry of Textiles has no specific housing scheme for textile workers. However, it has a Workshed-cum-housing Scheme for Handloom Workers under which Central assistance of Rs.18,000/- for a rural and Rs.20,000/- for an urban workshed-cum-house is given.

SHRIMATI S. G. INDIRA: I would like to know from the hon. Minister about the textile workers in India. There are a few States like Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat where the concentration of textile workers is quite high. Is the Government having any proposal to provide low-cost housing facility to the textile workers particularly in those States?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी , वैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की आवास के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं है लेकिन हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यशाला के साथ आवास की एक योजना हम चला रहे हैं जिसके बारे में हमने अपने उत्तर मे बता दिया है ।

SHRIMATI S. G. INDIRA: In the reply, it has been mentioned that the Government has a Workshed-cum-Housing Scheme for handloom workers under which Central assistance of Rs.18,000/- for a rural workshed-cum-house and Rs. 20,000/- for an urban, workshed-cum-house is given. I would like to know from the hon. Minister the number of schemes that has been provided to Tamil Nadu and the number of beneficiaries of those schemes. I would like the hon. Minister to provide us with the relevant data.

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी , तमिलनाडु में हम लोगों ने 5584 लोगों को इस योजना से लाभ पहुंचाया है और करीब 22 लाख रूपए इस पर खर्च हुए हैं । तमिलनाडु के बारे में इन्होंने पूछा तो इसका जवाब मैंने दे दिया है ।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या : सभापति महोदय , मैं आपके माध्यम से टेक्सटाइल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में वर्कशेड – कम –पक्का हाऊस का निर्माण काफी मात्रा में

नहीं किया गया है,यह मेरे प्रश्न का " ए " भाग है और बी यह है कि वारंगल में आज़मजाही मिल में हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो बुनकरों को देने के काबिल है लेकिन भारत सरकार ने वहां पर कोई भी स्कीम नहीं बनाई है। हम आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करते हैं कि कोई न कोई योजना बनाकर वहां वर्कशेड-कम-हाऊस बनाने की व्यवस्था करें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी , रामचन्द्रय्या जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इस पर हम विचार करेंगे।

Violations of Traffic Rules in Delhi

*47. SHRI NANA DESHMUKH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the drivers in Delhi flout the no-entry rule and drive at high speed at night resulting in frequent accidents and tragedies;

(b) whether the present strength of traffic police is sufficient to meet the traffic requirement in the city; and

(c) if so, the steps being taken by Government to man the roads in wee hours?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There have been instances in which the drivers were found to have violated the "No entry" instructions or exceeded the prescribed speed limit.

(b) and (c) The rapidly increasing volume of vehicular traffic in Delhi makes it necessary to review and strengthen traffic management in the City on a continuing basis. The Government have accordingly taken several measures to strengthen the Delhi Traffic Police. These include creation of additional posts as and when required and increased use of modern, scientific traffic regulatory devices.

श्री नाना देशमुख : सभापति जी , मेरा सवाल भी ऐसा विचित्र है कि जम्मू – कश्मीर में तो हमारे बड़े –बड़े अफसर बलि के बकरे बन रहे हैं लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है,यहां